विकलांग मंच

विकलांग समुदाय का मार्गदर्शक पाक्षिक

वर्ष : 31 अंक: 3	जयपुर 1 अगस्त, 2016	RNI No.: 46429/86 Po.Regn.No.:Jaipur City/207/2015-17	वार्षिक शुल्क: 50/- प्रति मूल्य: 2.50

विकलांग मंच के आजीवन/वार्षिक सदस्य बनें एवं दूसरों को भी इसके सदस्य बनने की प्रेरणा दें

विकलांग मंच

8/141, मालवीय नगर, जयपुर-302017

फोन:0141-2547156, 9351960369,9352320013, फैक्स:0141-4036350

E-Mail:vicklangmanch@ymail.com E-Mail:vicklangmanch@gmail.com

दिव्यांगों के लिए बनेंगे पूरे देश में चलने वाले स्पेशल यूनिवर्सल कार्ड : गुर्जर

कुरुक्षेत्र। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि दिव्यांगों के लिए पूरे देश में चलने वाले स्पेशल यूनिवर्सल कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक दिव्यांगों के कार्ड एक प्रदेश में ही मान्य होते थे। प्रदेश बदलने पर दोबारा कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांगों को धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन यूनिवर्सल कार्ड बनने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी।

वहीं, दिव्यांगों को बेहतर कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए कृत्रिम अंगों को बेहतर बनाने पर खर्च किए जाएंगे। ताकि दिव्यांगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निट में आयोजित ग्लोबल आईटी चैलेंज राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लेने आए थे। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया।

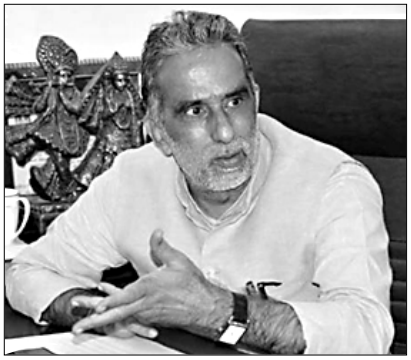

गुर्जर ने बताया कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए सुगम भारत अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत दिव्यांगों के आवागमन के लिए एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर 2019 तक लिफ्ट अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ईरा सिंघल ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में टॉप कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने दूसरे लोगों को ऐसे दिव्यांगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में चयनित दिव्यांग नवंबर 2016 में चीन में होने वाली अंतर राष्ट्रीय ग्लोबल आईटी चैलेंज 2016 की प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे।

योजनाओं का दिव्यांगों को मिलेगा सीधा लाभ

दिव्यांगसंस्थान के निदेशक केबीएस राव ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से दिव्यांगों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों को सरकार की ओर से उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। उनका ऑनलाइन डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है। एनआईटी के कार्यकारी निदेशक प्रो. वीके अरोड़ा ने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन करने से संस्थान का गौरव बढ़ा है। कार्यक्रम के चेयरमैन प्रो. सतहंस ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक प्रो. आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता से दिव्यांगों को मार्गदर्शन मिलेगा। इस मौके पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, सुशील राणा, विनीत क्षात्रा और डॉ. रामेंद्र सिंह मौजूद रहे।

दिव्यांगों को यात्रा से मना नहीं कर सकेंगी एयरलाइंस

दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन-3 पार्ट.एम एक में संशोधन कर इस संबंध में नए

नियम जारी किए गये हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन-3 पार्ट-एम एक में संशोधन कर इस संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति टिकट आरक्षित कराते समय ही एयरलाइंस को अपनी विशेष जानकारियों की जरूरत देता है तो एयरलाइंस इसके लिए मना नहीं कर सकतीं। विमान सेवा कंपनियों से तीन महीने के अंदर अपनी वेबसाइट पर प्रावधान करने के लिए कहा गया है ताकि विशेष रूप से सक्षम लोगों को उनकी जरूरत की सुविधाओं के चयन का विकल्प भी मिल सके वेबसाइट पर उन्हें ऐसे लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ विमान के आकार के कारण यदि कोई सीमा हो तो उसके बारे में भी बताना होगा।

डीजीसीए ने विमान सेवा कंपनियों से साफ शब्दों में कहा है कि वे या उनके एजेंट टिकट बुक कराने में दिव्यांगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। एक बार टिकट बुक हो जाने के बाद वे कोई इनक्वायरी भी नहीं कर सकते। वहीं दिव्यांगों को उड़ान के तय समय से कम से कम 48 घंटे पहले अपनी जरूरतों के बारे में एयरलाइंस को सूचित करना होगा ताकि वे सुविधाएँ उन्हें मुहैया कराई जा सकें।

हालाँकि यदि वे 48 घंटे से कम समय रहते भी एयरलाइंस को सूचित करते हैं तो एयरलाइंसों को समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इन जरूरतों में स्ट्रेचर, व्हील चेयर या जो लोग विमान की आम सीटों पर नहीं बैठ सकते उनके लिए बैठने की विशेष व्यवस्था शामिल है। हालाँकि यह भी निर्देश दिया गया है कि विमान में दिव्यांगों की संख्या केबिन क्रू की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें उन विकलांगों को नहीं गिना जाएगा जिनके साथ प्रशिक्षित इस्कॉर्ट मौजूद है। हवाई अड्डों को भी दिव्यांगों के लिए सुगम बनाने का निर्देश दिया गया है। टर्मिनल में संकेतक लगाने तथा दिव्यांगों के लिए पार्किंग में जगह आरक्षित करने के लिए भी कहा गया है। मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार पर रैम्प की उपलब्धता जरूरी किया गया है।

यूनियन बैंक अध्यक्ष ने किया नारायण रोटी वितरण वाहन का लोकार्पण

उदयपुर। यूनियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अरूण तिवारी ने कहा कि पीड़ितों और दिव्यांगों की सेवा ही सच्ची सेवा है। यूनियन बैंक सोश्यल फाउन्डेशन उनकी चिकित्सा और पुनर्वास के लिए संकल्पित हैं। वे नारायण सेवा संस्थान के बड़ी ग्राम स्थित सेवा महातीर्थ में यूनियन बैंक सोश्यल फाउन्डेशन की ओर से 'नारायण रोटी वितरण वाहन' का लोकार्पण कर रहे थे।

उन्होंने समारोह में दिव्यांग वीरेन्द्र लोधी को ट्राईसाइकिल व पंजाब की नीलम को व्हील चेयर भी प्रदान करने के साथ ही परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने स्वागत करते हुए बताया कि पिछले वर्ष संस्थान ने शहर की विभिन्न बस्तियों में निराश्रित, गांवों से मजदूरी की तलाश में

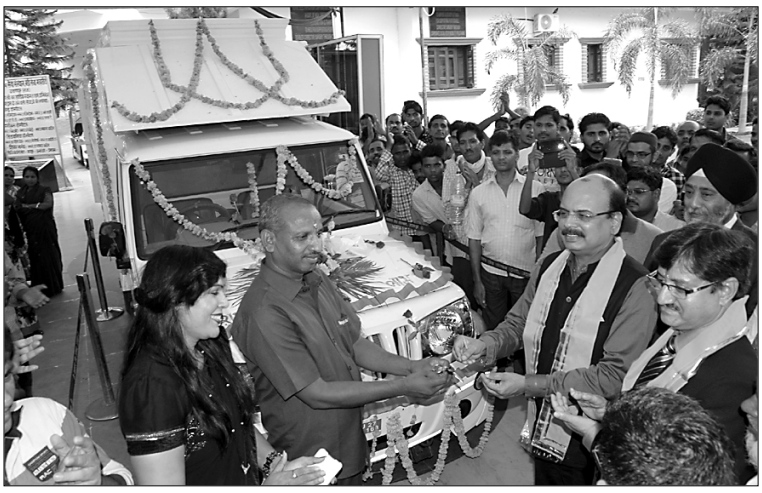

आने वाले व रैन बसैरों में रहने वालों के लिए दोनों समय का भोजन उन तक पहुंचाने का प्रकल्प शुरू किया। जिससे अब तक 1 लाख 50 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके है। संस्थान निदेशक वंदना अग्रवाल ने संस्थान द्वारा दिव्यांगों व निर्धनों के लिए चलाए जा रहे रोजगारोन्मुख प्रशिक्षणों की जानकारी दी।

निदेशक देवेन्द्र चौबीसा ने संस्थान की 30 वर्षीय सेवा यात्रा पर प्रकाश डाला। तिवारी ने पोलियो अस्पताल में नि:शुल्क ऑपरेशन के लिए दिव्यांगों की कुशल क्षेम भी पूछी और उन्हें फल वितरण किए। उनके साथ बैंक के दिल्ली अंचल के महाप्रबंधक ए.के दीक्षित, क्षेत्र प्रमुख आलोक कुमार, हिरण मगरी के ब्रांच मैनेजर दिव्येश कालरा एवं अधिकारी भी थे। संचालन महिन जैन ने किया।

विचार मंच

कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। **-चाणक्य**

मानवीय व्यवस्था

किसी समाज की सभ्यता मापने का एक पैमाना यह भी है कि वह दिव्यांगो के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो दौर चला गया, जब विकलांगता को व्यक्ति के पूर्व.जन्म के कर्मों का फल माना जाता था। आधुनिक धारणा है कि किसी एक अंग से कमजोर व्यक्ति भले आम लोगों की तरह ना जी पाता हो, लेकिन उसमें योग्यता या क्षमता की कमी नहीं होती। इसलिए उसकी शारीरिक कमजोरी को उसकी राह की बाधा नहीं बनने दी जानी चाहिए। इसी भावना के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया था। हैरतअंगेज है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग कहकर उन्हें सम्मान देने की पहल की है। वहीं उनकी सरकार ने ए और बी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में ऐसे लोगों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। अत: सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ा है। कोर्ट ने अब व्यवस्था दी है कि तीन फीसदी आरक्षण भारत सरकार के तहत आने वाले सभी पदों और सेवाओं में लागू होगा। केंद्र ने अपने निर्णय का आधार 1997 और 2005 के पत्रकों को बनाया था। उनके मुताबिक आरक्षण को सिर्फ ग्रुप सी और डी के पदों तक सीमित किया गया। लेकिन यह फैसला जातीय आरक्षण के लिए था। दिव्यांगों का मामला बिल्कुल अलग है। यह फर्क करने का विवेक केंद्र को खुद दिखाना चाहिए था। उसे ध्यान देना चाहिए था कि विकलांगों के हक में फैसला देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में दी गई अपनी ये व्यवस्था खुद बदल दी कि आरक्षण कुल पदों के पचास फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। तब कोर्ट ने साफ किया था कि इंदिरा साहनी मामले में लगाई गई सीमा सिर्फ पिछड़ी जातियों के आरक्षण के संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी कानून-1995 को आधार बनाते हुए दिया था। ए और बी श्रेणी के पदों पर उस निर्णय को ना लागू करने के केंद्र के परिपत्रों को अब उसने खारिज कर दिया है। इस तरह न्यायालय ने एक मानवीय व्यवस्था दी है। हालांकि यह फैसला केंद्रीय सेवाओं के लिए है, लेकिन अपेक्षित है कि राज्य सरकारें भी इसे अपनी सेवाओं में लागू करें। बेहतर तो यह होगा कि निजी क्षेत्र भी इसे मॉडल माने और अपने यहां इस पर अमल करे। उससे भारत अधिक आधुनिक एवं मानवीय समाज बन सकेगा।

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के साथ क्रूर मजाक

बड़े ही खेद एवं अफसोस के साथ व्यक्त करना पड़ रहा हैं कि शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों के अध्यापन कार्य हेतु विशेष शिक्षकों के मात्र 164 पद ही निकाले हैं। जिसमें 76 पद प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 तक तथा 88 पद द्वितीय लेवल कक्षा 6 से 8 तक के लिये हैं जिसमें 26 पद टी.एस.पी. क्षेत्र के निर्धारित किये गये हैं। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय विद्यालयो में विभिन्न श्रेणी के एक लाख चौबीस हजार आठ सौ पच्चपन दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत् हैं। जिन्हें उनकी भाषा में पढ़ाने हेतु 15,606 विषेष शिक्षकों की महती आवश्यकता अधिनियमानुसार हैं। वहीं दूसरी और शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, पी.डब्ल्यू.एक्ट 1995 आदि की अनदेखी करते हुये मात्र 164 पद निकालकर आवेदन पत्र 11 जुलाई 2016 से प्रारम्भ कर दिये गये हैं। ऐसा करके शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों एवं उनके परिवार के साथ मजाक किया हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 8 दिव्यांग बच्चों पर 1 विशेष शिक्षक का प्रावधान हैं। वहीं भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 के सैक्शन 13 में दिव्यांग बच्चों को सामान्य शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य कराये जाने पर सजा का प्रावधान किया गया हैं । विशेष शिक्षक का भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली में पंजीकरण होना चाहिये। अभी तक शिक्षा विभाग ने सन् 2006 में पहली बार 250 विशेष शिक्षकों के पदों की भर्ती निकाली थी और उसके बाद सन् 2012 में 637 विशेष शिक्षकों के पद निकाले। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती में मात्र 250 एवं 637 एवं सन् 2015 की भर्ती में मात्र 164 पद निकालकर दिव्यांग बच्चों, उनके परिजनों एवं विशेष शिक्षकों के साथ मजाक किया हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता हैं कि शिक्षा विभाग, दिव्यांगों के प्रति कितना सवेंदनशील हैं? जबकि सरकार के पास मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं वहीं प्रशिक्षित विशेष शिक्षक भी बड़ी संख्या में रीट अथवा टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं। सामान्य शिक्षकों की तुलना में विशेष शिक्षकों को दोहरा मापदण्ड पूरा करना पड़ता हैं। विशेष शिक्षकों को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में पंजीकरण करना अनिवार्य होता हैं और हर 5 साल बाद 100 अंकों का आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त कर पंजीकरण को रिनुवल कराना पड़ता हैं। यह प्रक्रिया सामान्य शिक्षक से दोहरा मापदण्ड है। मानवाधिकार आयोग, जयपुर ने समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर विशेष शिक्षकों के इतने कम पद निकालने पर एवं शिक्षकों को अन्य कार्य करवाने पर स्वंय प्रसंज्ञान लेकर शिक्षा विभाग एवं सरकार को नोटीस दिया हैं तथा अन्य विभागों ने भी दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के पद कम निकालने पर शिक्षा विभाग को नोटीस देकर जबाब माँगा हैं। दिव्यांगों, उनके परिजनों एंव सामाजिक संगठनों द्वारा बार-बार ज्ञापन देकर निरन्तर विशेष शिक्षकों की मांग की जाती रही हैं। उसके बावजूद यह दशा। **-देवेन्द्र कुमार शर्मा, सामाजिक कार्यकर्त्ता, जयपुर**

योजनाएं तमाम फिर भी दिव्यांग हलकान

लखनऊ। दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले की कई योजनाएं चलाने का दावा करती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन तक कितना पहुंच रहा है उसका कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में उ.प्र. में दिव्यांगों को तीन सौ रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। जबकि ग्राउंड लेवल पर उसकी हकीकत कुछ और है। खुद सरकारी मदद पाने वाले दिव्यांग सरकारी पेंशन मिलने की बात तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हर माह नहीं बल्कि तीन से चार माह में एक ही पेंशन मिलती है।

चिनहट के तीन किमी अंदर आगे ढेरा गांव निवासी जय सिंह विगत कई दिनों से अपनी ट्राई साइकिल के लिए भटक रहा है। जय सिंह का कहना है कि तीन वर्ष पहले उसे ट्राई साइकिल मिली थी। जिसकी अब हालत जर्जर हो गई है। उसकी मरम्मत के लिए वह अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा है। ट्राई साइकिल को बदलने के लिए वह कई दिन से लगातार बीस किमी ट्राई साइकिल से आता है। हर बार उसे कल आने की बात कहकर टरका दिया जाता है। जय सिंह ने बताया कि उसे तीन सौ रुपये पेंशन तो मिली है लेकिन हर महीने एकाउंट में पैसा नहीं आता है। तीन से चार महीने में एक बार ही एकाउंट में पैसा आता है।

सरकारी योजना के तहत मात्र तीन सौ रुपये दिव्यांग को प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। यह पेंशन उन्हीं को मिल सकती है जिनकी मासिक आय एक हजार रुपये से कम होनी चाहिए। आज की महंगाई के समय पर एक व्यक्ति के भरण पोषण के लिए क्या 300 रुपये प्रति माह पर्याप्त होगा। सरकार की यह योजना भी केवल खानापूर्ति जैसी है। क्यों कि पहले से एक हजार रुपये प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को मात्र तीन सौ रुपये की पेंशन से देकर उसे कितना मजबूत किया जा सकता है।

विकलांग जन विकास विभाग की सरकारी योजना में दुकान संचालन योजना में अब तक मात्र कुछ दिव्यांगों के ही आवेदन आये हैं। इस साल अब तक कुछ दिव्यांगों ने अपना कारोबार चलाने के लिए आवेदन किया है। जिसमें कुछ मामलों में उनके पास भूमि है जबकि कुछ मामलों में वह बिना जमीन के लिए कारोबार के लिए दुकान लगाने के लिए अनुदान राशि के लिए आवेदन किया है। विभाग के अनुसार हर वर्ष सैकड़ों दिव्यांग कारोबार चलाने के लिए आवेदन करते हैं। उनके डॉक्यूमेंट की जांच के बाद प्रक्रिया के तहत ही उन्हें चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लोन दिया जाता है।

जिस दिव्यांग की मासिक आय एक हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है उन्हें सरकार तीन सौ रुपये प्रति माह की दर से भरण पोषण के लिए अनुदान देती है। यह राशि दिव्यांग के बैंक एकाउंट में सीधे जाती है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग को उसकी आवश्यकता के अनुसार 5000 की सीमा तक के कृत्रिम अंग या सहायता उपकरण निशुल्क दिया जाते है। ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को यह सुविधा दी जाती है जिनकी मासिक आय एक हजार से अधिक न हो।

इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े में से यदि पति दिव्यांग है तो 25 हजार रुपये और पत्नी या पति, पत्नी दोनों दिव्यांग है तो 50 हजार की धनराशि अनुदान के रुप में प्रोत्साहन स्वरुप दी जाती है।

उद्यमी दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए बीस हजार तक की धनराशि निजी भूमि पर दुकान निर्माण के लिए दी जाती है। जिन दिव्यांग के पास अपनी भूमि नहीं है, उन्हें दुकान संचालन के लिए दस हजार रुपये दिये जाते है। यह राशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रुप में होती है।

इसके अलावा भी सरकार की बहुत सी योजना है जो दिव्यांग के लिए है। जैसे विकलांग निवारण के लिए शल्य चिकित्सा के लिए एक वर्ष में अधिकतम 8 हजार रुपये का अनुदान, राज्य परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों को नि:शुल्क यात्रा, शासकीय सेवा में दिव्यांग को आरक्षण की व्यवस्था और विशिष्ट दिव्यांगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के साथ-साथ जलकर और हाउस टैक्स में दृष्टिहीन और दिव्यांग को सौ फीसदी से लेकर पचास फीसदी तक छूट प्रदान की भी व्यवस्था है।

दिव्यांगों को स्वनिर्भर बनाता है चेशायर होम्स

कोलकाता। लिवलीहुड रिसोर्स सेंटर ऑफ चेशायर होम्स, कोलकाता शाखा की ओर से दिव्यांगों को प्रोत्साहित व जागरूक करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत, परीक्षण संस्थान एवं एनजीओ से जुड़े विभिन्न अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बताया गया कि उनकी ओर से समुदाय आधारित सेवाओं के लिए दो प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं, पहला दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा और दूसरा जीविका संसाधन केंद्र, जो दिव्यांग व्यस्कों के लिए जीविका की सुविधा प्रदान कराता है।

इसका मुख्य उद्देश्य 18-45 वर्ष की आयु के दिव्यांगों के लिए जीवनयापन के अवसर प्रदान करना है। संस्था यह कार्यक्रम दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करती है। इसके लिए उसे एसेंचर लिमिटेड से फंड प्राप्त होता है। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में हमलोगों ने कारपोरेट और बीपीओ सेंक्टरों में करीब 350 दिव्यांगों को सार्थक नौकरियां दिलायीं। इसके लिए संस्था ने उन्हें सरकार और निजी प्रशिक्षण केंद्रों में आधारभूत और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये।

चेशायर होम्स इंडिया की कोलकाता इकाई लियोनार्ड चेशायर (एलसीडी) का एक सदस्य संगठन है। अभी यह 56 देशों में दिव्यांगों की सेवा और पुनर्वास का काम कर रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र के सहायक निदेशक और विकलांगता आयुक्त अभिवन चंद्रा समेत वीआरसीएच के सहायक निदेशक डीएन गायत्री, विशेष रोजगार क्षेत्र के संयुक्त निदेशक शिवानी भट्टाचार्य, क्षेत्रीय प्रमुख रेवती रूकमणि, सहायक विकलांगता आयुक्त गौतम दास, प्रोजेक्ट मैनेजर देवब्रत बनर्जी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

नेत्रदान महादान

नेत्रदान किसी भी आयु, लिंग या रक्त ग्रुप का हो सकता है।

विकलांग मंच कार्यालय: प्लाट नं. 141, सेक्टर-8, मालवीय नगर, जयपुर-302017, फोन:0141-2547156. फोटो टाइपसेटिंग: टास्क ग्राफिक्स (मोबा.:9828278728)। मुद्रित: श्रीराम आफसेट, जोरावरसिंह गेट बाहर, आमेर रोड, जयपुर। संरक्षक: डी.आर.मेहता (रिटा.आईएएस)। प्रधान संपादक: एम.आर.सिंघवी (रिटा.आईआईएस)। प्रकाशक मुद्रक एवं सम्पादक: एन.के.खत्री। संपादकीय सलाहकार:डॉ. अरुण माथुर। हाडोती अंचल ब्यूरो प्रमुख: अर्जुन देव चद्डा, कोटा। प्रबन्धक:धर्मपाल। E-Mail:vicklangmanch@ymail.com / vicklangmanch@gmail.com

चिकित्सा शिविर में सैकड़ों लाभान्वित

उदयपुर। रामपुरा चौराहा पर अमर क्लिनिक द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। जिसमें नाई, बूझड़ा, पई, अलसीगढ़, सज्जन नगर, रामपुरा उबेश्वर आदि गांवों के लोगों ने अनुभवी चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही बी.पी., ब्लड शुगर एवं अन्य रोगों की जांच करवाई एवं नि:शुल्क दवाईयां प्राप्त की। शिविर का उद्घाटन सुप्रसिद्ध अस्थिरोग विषेषज्ञ डॉ. ए.एस. चुण्डावत ने किया। विशिष्ट अतिथि नारायण सेवा संस्थान की निदेशक श्रीमती वंदना अग्रवाल थी। शिविर आयोजक डॉ. घनश्याम पाल ने बताया कि शिविर में डॉ. चुण्डावत के साथ ही डॉ. गौरव वधावन, डॉ. निरंजन सोनी व डॉ. निकिता वधावन के साथ ही विभिन्न रोग विषेषज्ञों ने रोगियों की जांच कर परामर्श एवं दवाईयां प्रदान की।

दिव्यांगों के लिए बनेगा नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स

ग्वालियर-दिव्यांगों के खेल एवं उनकी प्रतिभा निखारने के लिए ग्वालियर में नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेगा। इसके लिए जगह तय कर ली गई है और बहुत जल्द कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए डिजाइन, टेंडर की कार्रवाई होगी। ये कॉम्पलेक्स ट्रिपल आईटीएम के सामने 15 एकड़ जमीन पर तैयार होगा। यहां दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही दिव्यांगों को विभिन्न खेल गतिविधियों की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके लिए जगह तय कर उसका प्रस्ताव राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग को भेज दिया गया है और वहां से ये प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग के पास जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगों को खेल जगत की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश में 4 दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाए जा रहे हैं। ये कॉम्पलेक्स ग्वालियर, पंजाब के जीरखपुर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम व ओडिशा में बनाए जाएंगे। प्रदेश का दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स ग्वालियर में शुरू होगा।

स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में खेल आयोजनों के अलावा दिव्यांग स्टूडेंट्स को खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ताकि दिव्यांग खेलों में पारंगत होने के बाद यहां का नाम रोशन करें। प्रशिक्षण देने के लिए कॉम्पलेक्स में पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी।

दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए पहले 7.5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव जा चुका है। लेकिन इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत है। 7.5 एकड़ जमीन का और नया प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। ये कॉम्पलेक्स 15 एकड़ में तैयार होगा। ट्रिपल आईटीएम के सामने दिव्यांग स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाना है जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार देशभर में ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बना रही है इनमें से एक ग्वालियर को मिला है।

सूचना

फैमिली ऑफ डिसेबल्ड (एफओडी) सन 2001 से प्रति वर्ष प्रतिभाशाली दिव्यांग चित्रकारों तथा मूर्तिकारों की कृतियों की प्रर्दशनी बियोंड लिमिट्स का आयोजन दिल्ली की प्रतिष्ठित कलादीर्घा मे आयोजित करती आ रही है इस वर्ष भी बियोंड लिमिट्स 2016, 1 दिसम्बर से 8 दिसम्बर तक आयोजित की जाएगी इसमें भाग लेने के इच्छुक कलाकार एफओडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में सम्पर्क करें।

फैमिली ऑफ डिसेबल्ड
150, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोन नं 01141570140, 45129935
Mail : contact@familyofdisabledd.org, rajinder.johar@familyofdisabled.org

दो दिव्यांग थाईलैंड में करेंगे माउंटेनरिंग

चंडीगढ़। जिनमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत हो उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। बस इरादे पक्के होने चाहिए। जी हां ऐसा ही कुछ कर दिखाया है शहर के दो ऐसे दिव्यागों ने जो शीरिरिक तौर पर फिट नहीं, लेकिन थाईलैंड में माउंटेनरिंग करेंगे। शहर के दो दिव्यांगों का नाम इंटरनैशनल माउंटेनरिंग के लिए चुना गया है। ये दोनों दिव्यांग थाईलैंड में माउंटेनरिंग के लिए जाएंगे। गौरतलब है सोशल वैल्फेयर, वूमन एंड चाइल्ड डिपार्टमैंट द्वारा इंडियन माउंटेनरिंग फाऊंडेशन के सहयोग से शहर के 30 दिव्यांगों का बैच 14 मई को चंडीगढ़ से मनाली के लिए रवाना हुआ था। इसमें उन दिव्यांगों के साथ उनके कोच भी गए थे। दिव्यांगों को मनाली के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में रॉक क्लाइम्बिंग को लेकर ट्रेनिंग ली थी। इनमें से दो ऐसे थे, जिनका नाम इंटरनैशनल माउंटेनरिंग के लिए चुना गया था। इनमें सीताराम व अनमों का नाम शामिल था। इसके बाद 20 जून को इन दोनों को दिल्ली में आई.एम.एफ में टैस्ट के लिए भेजा गया था।

मंज़िल मिले या न मिले ये मुक़द्दर की बात है।
हम कोशिश भी न करें ये गलत बात है॥
क्या हम एक पोस्ट कार्ड नहीं लिख सकते।
प्रधान मंत्री जी को अपने दिव्यंजनो के लिये ॥
देश के सभी स्कूलों में
विशिष्ट अध्यापको की नियुक्ति के लिये॥

हाईटेक जमाने के साथ मोटर राइड्स ट्राइसाइकिल से दौड़ेंगे दिव्यांग

चित्तौड़गढ। हाईटेक जमाने के साथ दौड़ती-भागती दुनिया में भला दिव्यांग भी क्यों ट्राइसाइकिल से ही रेंगते हुए चलें। वे भी बाकी लोगों के साथ कदमताल कर सकें इसके लिए चित्तौड़गढ़ जिले ने अभिनव अभियान हाथ में लिया है। 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को मोटर राइड्स ट्राइसाइकिल निशुल्क दी जाएगी। पहले चरण में 200 वयस्क दिव्यागों को ऐसे वाहन देने का लक्ष्य है। दिव्यांगों के चयन के लिए गांव में अटल सेवा केंद्रों तथा नगरीय क्षेत्र में वार्डों में कैंप लगाकर सर्वे किया जा रहा है। वैसे तो प्रत्येक दिव्यांग को सरकारी सहायता से लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन यहां इसके साथ ही 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों का अलग से सर्वे हो रहा है। आम तौर पर सरकार या स्वयंसेवी, सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग जैसी वस्तुएं देकर संबल दिया जाता है। जिले में कलेक्टर इंद्रजीतसिंह की पहल पर इस अभियान के तहत पहली बार वयस्क दिव्यांगों को मोटर राइड्स ट्राइसाइकिल मिलेंगी, जो प्रदेश में नया उदाहरण बनेगा। सुगम्य भारत अभियान के तहत पंचायतों और शहरी क्षेत्र में दिव्यांग सर्वे के लिए कैंप किए जा रहे हैं। संबंधित एसडीएम बीडीओ को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

पात्र दिव्यांगों के बीपीएल कार्ड जारी बनवाने की मांग

अन्ता (बारां)। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आफाक अहमद खान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर जिले के पात्र दिव्यांगों के बीपीएल कार्ड जारी बनवाने की मांग की है ताकि यह दिव्यांग सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

सेठी के निधन पर शोक

दिल्ली-तरुण मित्र परिषद ने एक विशेष सभा मे महावीर प्रसाद जैन सेठी के 9 जुलाई को निधन पर शोक व्यक्त किया। परिषद के महासचिव अशोक जैन ने कहा कि महावीर बाबू एक प्रसिद्ध समाजसेवी के रूप मे विख्यात जैन समाज के सर्वमान्य नेता थे। तरुण मित्र परिषद ने सन् 1998 मे श्री सम्मेद शिखर जी, मधूबन (झारखंड) मे एक विराट नेत्र शिविर का आयोजन किया था जिसमें उन्होने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था तथा प्रति वर्ष आयोजित प्रत्येक कैम्प मे उनका सहयोग सराहनीय रहा । श्री सम्मेद शिखर जी मे विख्यात महावीर बाबू दिगम्बर जैन बीसपंथी कोठी के मंत्री, ऑल इन्डिया तीर्थक्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष, तरुण मित्र परिषद के सहयोगी, श्री सम्मेद शिखर जी मे विद्यमान सभी संस्थाओं से जुडे हुए थे।

विकलांग मंच वेबसाइट पर भी

विकलांग मंच के सभी सुधि पाठकों से निवेदन है कि आपका राष्ट्रीय पाक्षिक समाचार पत्र 'विकलांग मंच' अब वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पाठक नवीनतम अंक के लिए www.lbdvs.org पर अवलोकन करें।

-प्रबंधक

सुधि शुभचिंतकों की सूचनार्थ

समाज के सर्वहारा वर्ग का प्रकाशन विकलांग मंच समाज, शासन एवं नि:शक्तजनों के मध्य सेतु माध्यम का अकिंचन प्रयास है। देश के अन्य राज्यों सहित राजस्थान में नि:शक्तजनों के कल्याणार्थ किए गए कार्यों की जानकारी समाज के सामने रखने का प्रकाशन का पूरा प्रयास रहता हैं। उदारमना महानुभावों के सहयोग से व्यापक प्रसार संख्या वाले इस प्रकाशन की नि:शक्तजनों की सेवा में महती भूमिका है।

आपश्री से निवेदन है कि कृपया आप स्वयं एवं अपने परिचितों को विकलांग मंच का सदस्य (सहयोग राशि आजीवन 500/- अथवा वार्षिक 50/-रूपये मात्र) बनने के लिए प्रेरित करें। आपश्री अपनी सहयोग राशि मनीआर्डर/ डीडी/ पोस्टल आर्डर/ एट पार चेक (जो विकलांग मंच जयपुर के नाम देय हो) द्वारा निम्न पते पर भिजवा सकते हैं। इसके अलावा आपश्री अपनी सहयोग राशि भारतीय स्टेट बैंक में विकलांग मंच के खाता संख्या 32093997756 में भी सीधे जमा करा कर मोबाइल फोन 09352320013 अथवा ई-मेल vicklangmanch@gmail.com पर मैसेज (अपने डाक पते सहित) देने का अनुग्रह करें।

प्रबंधक, विकलांग मंच
8/141,मालवीय नगर, जयपुर-302 017
फोन : 0141-2547156, फैक्स : 0141-4036350

लुई-ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान

प्रगति की ओर बढ़ते कदम...

सहयोग की नींव पर समाज की इमारत खड़ी है। चराचर जगत के लिये समाज जरुरी है, तो समाज निर्माण के लिए सहयोग आवश्यक है। यही आधार है किसी भी संगठन के उदय होने का। नियती का क्रूर प्रहार करें या जीवन की विडम्बना, मानव शरीर की सबसे आवश्यक व नश्वर संसार को दृष्टिगत कर सकने वाले अंग- 'आंख' की ज्योति का लुप्त हो जाना। उस पर स्वयं की अनभिज्ञता, समाज व परिवार में व्याप्त मानसिकता की कमी, नेत्रहीनों को अजीब सी कुण्ठाग्रस्त जिन्दगी जीने को बेबस कर देती है। आज, कुपोषण व गरीबी की वजह से दृष्टिरोगों से ग्रसित होकर, हजारों नौनिहाल असमय ही अन्धेरी जिन्दगी के दास हो जाते हैं। यह संख्या लाखों को पार कर गयी है। अकेले, राजस्थान प्रदेश में ही अनुमानित 7 लाख के करीब नेत्रहीन भाई-बहिन अपनी कष्टप्रद जिन्दगी को जैसे-तैसे गुजार रहे हैं। ये नेत्रहीन भाई-बहिन, नगरों की गलियों, मोहल्लों या गांवों-ढाणियों, दूरस्थल अंचलों में बिखरे पड़े हैं। इनके पुनर्वास व उत्थान के लिए समन्वय व सामंजस्य की प्रथम आवश्यकता है। इनके लिए सर्वेक्षण कर, इनको समन्वित करना बड़ा दुरुह कार्य है। परन्तु कुछ उत्साही समाजसेवी कार्यकर्त्ताओं व नेत्रहीन बंधुओं द्वारा इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हाथ में लिया गया तथा 4 जनवरी, 1981 को दृष्टिहीनों के पथ प्रणेता लुई-ब्रेल की जयन्ती पर लुई-ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजस्थान, जयपुर के यहां से पंजीकृत है जिसका पंजीकरण क्रमांक 393/83-84 है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी एवं विदेशी अनुदान के लिए एफसीआरए के अन्तर्गत पंजीबद्ध है। संस्थान को भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसका निरीक्षण केन्द्रीय व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

हॉस्टल में सुबह की प्रार्थना के साथ प्रशिक्षण की शुरुआत।

संस्थान के उद्देश्य

1. दृष्टिहीनों को उन्नतिशील बनाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना।
2. दृष्टिहीनों में समन्वय सामंजस्य स्थापित करने हेतु हरसम्भव प्रयास करना व इस हेतु अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।
3. दृष्टिहीनों का जीवन स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से उनके शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. दृष्टिहीनों को रोजगार दिलाने का यथासम्भव प्रयत्न इस दृष्टि से उन्हें लघु व कुटीर उद्योगों में संस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस निमित्त विभिन्न संस्थानों से उन्हें अनुदान सहायता दिलवाने की व्यवस्था करना।
5. ग्रामीण अंचलों में रहने वाले दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा रोजगार के स्त्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना।
6. दृष्टिहीनों के सर्वेक्षण के लिए सभी सम्भव योग्य स्त्रोतों से सहायता लेकर, आंकडे एकत्रित कर संग्रह करना व समय-समय पर इनको उपयोग में लेना।
7. जन साधारण को दृष्टिहीनों की स्थिति, इनके द्वारा सम्पादित किये जाने योग्य कार्यकलापों की जानकारी कराने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों, सभाओं आदि का आयोजन करना। प्रचार सामग्रियों,

पोस्टर, होर्डिंग्स, चलचित्रों के माध्यम से प्रचार करना।

8. दृष्टिहीनों के लिए साहित्यादि का प्रकाशन करना व इनको पढ़ने आदि की सुविधा हेतु पुस्तकालयों, वाचनालयों आदि की स्थापना करना।
9. दृष्टि रोगों की जांच करवाना व इनकी रोकथाम के उपाय करना व समुचित व्यवस्था करना।
10. दृष्टिहीनों के नियोजन हेतु मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना करना तथा इस सन्दर्भ में उन्हें हरसंभव सहायता दिलाने का प्रयास करना।
11. ऐसे संस्थानों व सेवा केन्द्रों की स्थापना करना जहां इनकी समस्याओं के लिए विचार-गोठियां, सम्मेलन, बैठक आदि आयोजित की जा सके। इन्हीं केन्द्रों के माध्यम से इनके लिए आंकडे एकत्रित करना व सूचना हेतु प्रसारित करना।

नेत्रदान

इसे बनाएं अपने परिवार की परम्परा

नेत्रदान के बारे में तथ्य

-- किसी भी आयु का कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है।
-- एक व्यक्ति द्वारा दान की गई आंखें दो नेत्रहीनों को रोशनी दे सकती है।
-- मृत्यु के 4-6 घंटे तक आंखे दान देने के योग्य रहती हैं।
-- आंखें खरीदी अथवा बेची नहीं जा सकती।
-- नेत्रदान का प्रण पहले न किया हो तो भी नेत्रदान किया जा सकता है।
-- इस प्रक्रिया में केवल 15-20 मिनट लगते हैं।
-- सभी धर्म नेत्रदान का समर्थन करते हैं।

संस्थान द्वारा संचालित प्रवृत्तियां

1. आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र: संस्थान द्वारा जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित बढ़ारणा ग्राम में दृष्टिहीन आवासीय केन्द्र संचालित किया जा रहा है। यह भूखण्ड उदारमना समाजसेवियों द्वारा दान में प्रदत्त कराया गया है। जिसका शिलान्यास 31 मई, 1996 को संत शिरोमणि श्री श्री 1008 स्वामी नारायण दास जी महाराज (त्रिवेणीधाम) के करकमलों से हुआ। इस भूखंड पर जनसहयोग से अब तक 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण का प्रथम व द्वितीय चरण पूरा कराया गया। इस भवन में वर्तमान में 30 दृष्टिहीन बंधुओं के आवास एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की हुई है। दृष्टिहीन बंधुओं को चॉक-मोमबत्ती, लिफाफे, फाईल पैड, केनिंग हैंडलूम आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां इनको आवास, भोजन और दैनदिन सुविधाएं नि:शुल्क प्रदत्त है।

प्रशिक्षणार्थी पुस्तकालय में अध्ययन करते हुए।

2. कम्प्यूटर, ब्रेल आशुलिपि एवं टंकण प्रशिक्षण: संस्थान द्वारा आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर, ब्रेल आशुलिपि एवं टंकण का आधुनिक उपकरणों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
3. ब्रेल पुस्तकालय एवं ध्वनांकित कैसेट लाइब्रेरी: संस्थान द्वारा संचालित ब्रेल पुस्तकालय एवं ध्वनांकित (ऑडियो) कैसेट्स लाइब्रेरी में ब्रेल लिपि की किताबें और साहित्य से संबंधित आडियो कैसेट्स का संकलन है जिससे आवासीय दृष्टिहीन बंधुओं के साथ जयपुर शहर और अन्य जिलों के नेत्रहीन लाभान्वित हो रहे हैं।
4. संस्थान नेत्रहीनों को चिकित्सा, प्रमाण-पत्र, रोड़वेज-हवाई जहाज यात्राओं के लिए कन्शेसन की कार्यवाही, नौकरी/प्रशिक्षण/शिक्षण के लिए अग्रेषण कार्यवाही (प्लेसमेंट), आवास व अन्य दी जा सकने वाली सुविधाओं में प्राथमिकता दिलाये जाने की कार्यवाही करता है। संस्थान, नेत्रहीनों को सरकारी परिपत्रों/योजनाओं की जानकारी सुलभ कराता है व क्रियान्विति हेतु प्रयास करता है। संस्थान द्वारा नेत्रहीनों के विकास के लिए चरण-प्रति-चरण कार्यक्रम सम्पादित किये जा रहे हैं। स्त्रोतों की उपलब्धि के साथ ही नये-नये कार्यक्रमों की क्रियान्वित करने के लिए संस्थान संकल्पबद्ध है।

कम्प्यूटर कक्ष में प्रशिक्षण लेते प्रशिक्षणार्थी।

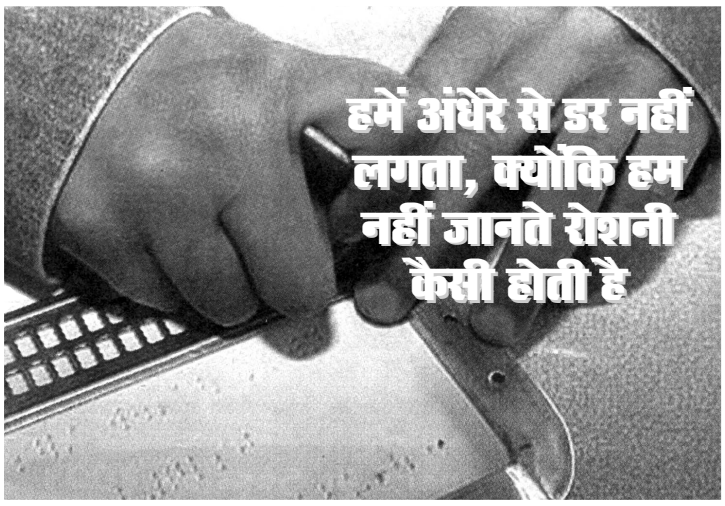

इसके बाद भी दृष्टिहीनों में एक सक्षम नागरिक बनने की असीमित क्षमता है। उन्हें चाहिये विशेष प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ। सक्षम नागरिकों का दायित्व है, इस कार्य में सहयोग करना।

36 वर्षों से दृष्टि बाधितों की सेवा में

सतत प्रयत्नशील

लुई-ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान

:प्रवृत्तियां:

- ब्लाइंड रिलीफ सेंटर
- आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण एकांश
- ब्रेल लायब्रेरी

दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं के लिए

लुई-ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित

दृष्टिहीन आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र

-: हमारे द्वारा देय सेवाएँ :-

- प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ब्रेललिपि द्वारा अध्यापन
- कंप्यूटर टाईपिंग एवं शॉर्टहैंड द्वारा स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण
- नि:शुल्क भोजन एवं आवास व्यवस्था
- नि:शुल्क परामर्श केन्द्र

दृष्टिहीन बालक नहीं जानते रोशनी कैसी होती है

इसके बाद भी दृष्टिहीनों में एक सक्षम नागरिक बनने की एक असीमित क्षमता है। उन्हें चाहिये विशेष प्रशिक्षण एवं सुविधाएं। सक्षम नागरिकों का दायित्व है, इस कार्य में सहयोग करना।

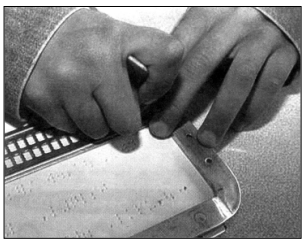

एम.पी. गुप्ता	ओमप्रकाश अग्रवाल	जयप्रकाश गुप्ता
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

लुई-ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान

एच-32, बढ़ारणा, टेलीकॉम ट्रेनिंग सेन्टर के पीछे, वाया रोड नं. 14, वी.के.आई. एरिया, जयपुर-302013, फोन:0141-4023328, 2235738, मो.:09314561988 (सचिव)

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 109 वें स्थापना दिवस पर किए अनेक कल्याणकारी आयोजन

जयपुर। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 20 जुलाई को अपनी स्थापना के 108 वर्ष पूरे किए। वर्ष 1908 में इसी दिन बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी राव गायकवाड तृतीय ने बैंक की स्थापना की थी। इस अवसर पर बैंक के जयपुर स्थित अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। प्रात: काल बैंक के स्टाफ सदस्यों की पर्यावरण सुरक्षा एवं श्रेष्ठ ग्राहक सेवा लक्ष्य पर केंद्रित जयपुर के जवाहर सर्किल से बैंक के दुर्गापुरा स्थित बड़ौदा भवन तक विशाल रैली निकाली गई। रैली में शामिल स्टाफ़ सदस्यों को संबोधित करते हुए बैंक के राजस्थान अंचल के प्रमुख एस.के.अरोड़ा ने बैंक के स्थापना दिवस पर अपनी सेवा द्वारा बैंक के ग्राहकों को सेवा का सर्वोत्कृष्ट एहसास दिलाने हेतु समर्पित प्रयास करने के संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि आज के दिन बैंक पूर्णत: स्वचालित खाता खोलने वाले कियोस्क का शुभारंभ कर रहा है जिसके उपयोग द्वारा ग्राहक तत्काल अपना खाता खोल पाएंगे और डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आज बैंक टेबलटॉप एटीएम, मोबाइल वैलेट, बड़ौदा एम क्लिरप, उन्नत मोबाइल बैंकिंग ऐप की भी शुरूआत कर रहा है। अन्य आयोजनों में बैंक की ओर से होमियोपैथी विश्वविद्यालय जयपुर में वृक्षारोपण किया गया। स्कूलों में छात्रों के लिए दोपहर का भोजन (मिड डे मील) उपलब्ध कराने वाली संस्था अक्षय पात्र फाउंडेशन को चार गाड़ियां दान स्वरूप प्रदान की गई। जयपुर स्थित अपना घर चाइल्ड केयर में बच्चों के लिए बैंक की ओर से उपयोगी स्टेशनरी-सामग्री का वितरण किया गया। बैंक के बड़ौदा भवन में स्टाफसदस्यों एवं उनके परिवार जनों के लिए बैंक के बीमा साझीदार कंपनियों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एवं मैक्स बूपा लाइफइंश्योरेंस के सहयोग से स्वास्थ्य जांच एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। दिन भर चलने वाले इन कार्यक्रमों की श्रृंखला के समापन अवसर पर बैंक के जयपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक पी.सी.सोनी ने अपने संबोधन में सभी स्टाफ सदस्यों को टीम भावना के साथ काम करते हुए आने वाले वर्षों में बैंक को नई बुलंदियों तक ले जाने का आह्वान किया।

अब दिव्यांगों को यूनीक आइडी का सहारा देशभर में समान रूप से मिलेंगी सुविधाएं

एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं होगा बदलाव

लखनऊ। यदि आप दिव्यांग हैं और आपको प्रदेश के बाहर जाना है और रियायत का लाभ न मिलने को लेकर परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होने वाली है। एक परिचय पत्र आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। इस नई योजना को लागू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं।

विशेष लोगों को दिव्यांग की श्रेणी में रखने के बाद अब उनका समान परिचय पत्र बनाकर परेशानियां दूर करने की कवायद शुरू हो गई है। यूनीक डिसएबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) के माध्यम से न केवल दिव्यांग प्रमाणपत्रों में एकरूपता आएगी बल्कि सही दिव्यांगों को सुविधा का लाभ मिलेगा। लखनऊ मंडल को मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। सभी दिव्यांगों को यूडीआइडी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 8.5 लाख दिव्यांगों को इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में 35 लाख दिव्यांगों को चिह्नित किया गया है। इस नई व्यवस्था से प्रदेश के बाहर भी उन्हें परिवहन की सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेंगी। सूबे के बाहर जाने पर परिवहन की सुविधा नहीं मिलती थी। प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए आवेदन करने में भी उन्हें आसानी होगी। यूडीआइडी से किसी भी दिव्यांग की पड़ताल भी आसानी से की जा सकेगी।

ऐसे बनेगा यूडीआइडी

ऐसे दिव्यांग जिन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है, उनका विवरण जिला विकलांग जन विकास कार्यालय में डिजिटल किया जाएगा और फिर उनका परिचय पत्र बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले दिव्यांगों को तुरंत यूडीआइडी दे दी जाएगी। यह सुविधा नि:शुल्क होगी।

विकलांग जन विकास विभाग के संयुक्त निदेशक अखिलेंद्र कुमार ने बताया कि सभी मंडलों में यूडीआइडी बनाया जाएगा। राजधानी में इसकी शुरुआत सबसे पहले होगी। राजधानी में प्रशिक्षण की शुरुआत अगले सप्ताह से हो जाएगी।

एक बार यूडीआइडी बनने पर दिव्यांगों के प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकेगा। अभी तक दिव्यांग अपने जिले के बजाय दूसरे जिले से दिव्यांगता के प्रतिशत में बदलाव करा लेते थे और सुविधाओं का लाभ ले लेते थे।

समय निकाल बुजुर्गों के साथ वक्त बिताएं

लुधियाना। डिप्टी कमिश्नर रवि भगत ने शहर के समाज सेवी संगठनों से अपील की कि वो रोजाना अपना कुछ टाइम निकालकर बुजुर्गों के साथ कुछ वक्त जरूर बिताएं। वहीं, उनके बच्चों को भी प्रेरित करें कि बुजुर्गों का सत्कार करें। वो सराभा नगर स्थित रेडक्रॉस सीनियर सिटीजन होम में बुजुर्गों को गद्दे, सिरहाने, चादरें और अन्य सामान बांटने आए थे। पिछली बार यहां दौरे के वक्त बुजुर्गों ने उन्हें इस जरूरत के बारे में बताया था। इसे लुधियाना सिटीजन कौंसिल संस्था की मदद से उन्होंने पूरा कर दिया। डीसी ने कहा कि मौजूदा वक्त में समय और सम्मान की कमी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जो बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमें राह दिखाने वाले होते हैं, जिस वजह से बच्चों को बुजुर्गों को सम्मान देकर उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चों के पास अपने मां-बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के इकलौते जीवन को सहारा देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक महीने में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, सरकारी दफ्तरों में भी बुजुर्गों के साथ औरतों और दिव्यांगों को तरजीह, सम्मान देने के निर्देश जारी किए जाएंगे। डीसी ने कहा कि पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को सही ढंग से लागू करने के लिए बैठकें की जाएंगी। वहीं, बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों से सीधा संपर्क बनाते हुए 100 साल से अधिक उम्र के 66 बुजुर्गों का हर तीन महीने बाद मुफ्त मेडिकल जांच निरीक्षण करने के साथ उनका जरूरी इलाज भी किया जाता है।

पाकिस्तान से आई गीता अब ट्रेन में बैठकर तलाशेगी फैमिली, रेलवे देगा गेस्ट का दर्जा

नई दिल्ली। आठ महीने पहले पाकिस्तान से भारत लौटी गीता की फैमिली का अब तक पता नहीं लग सका है। बता दें कि गीता न बोल सकती है और न सुन सकती है। गीता अब ट्रेन के जरिए फैमिली को खोजना चाहती है। उसकी यह सलाह फॉरेन मिनिस्ट्री ने मान ली है। इस बारे में एक प्रपोजल रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि रेल मंत्रालय इस सुझाव को मान लेगा। जैसे ही गर्मी कम होगी। गीता की यात्रा शुरू हो जाएगी। रेलवे से यह रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो गीता को गेस्ट का दर्जा देकर उसे सभी फेसेलिटीज दिलाई जाएं। माना जा रहा है कि सफर के दौरान गीता के साथ उसके कुछ असिस्टेंट भी रहेंगे। गीता बोल और सुन नहीं सकती है इसलिए असिस्टेंट के अलावा एक इंटरप्रेटर भी गीता के साथ होगा ताकि लोगों को गीता की बातें समझाई जा सकें।

झारखंड़ में दिव्यांगों को 3 फीसदी आरक्षण

रांची। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों को राज्य सरकार के सभी तरह के पदों पर होने वाली नियुक्ति और सभी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में तीन प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी। बैठक की जानकारी देते हुए एसएस मीणा ने बताया कि दिव्यांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियुक्ति के लिए विज्ञापित कुल पदों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जायेगा। बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह मीटिंग रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई।

नंगे पैर दौड़ने से बढ़ सकती है याददाश्त

वाशिंगटन। एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार नंगे पैर दौड़ना याददाश्त बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले 72 लोगों पर शोध किया। जो नंगे पैर दौड़े उनकी याददाश्त पहले की तुलना में 16 प्रतिशत बेहतर पाई गई। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि नंगे पैर दौड़ने के लिए जो सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है, उसके कारण याददाश्त पर ऐसा प्रभाव हो।

मूक बधिर विद्यार्थियों ने लिया राज्य स्काउट प्रशिक्षण

जयपुर। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोदार उ.मा. विद्यालय जयपुर के आठ मूक बधिर विद्यार्थियों ने राजस्थान राज्य स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय के सहयोग से आयोजित पांच दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण में भाग लिया। विद्यालय के स्काउट प्रभारी योगेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि इन आठ मूक बधिर विद्यार्थियों ने सामान्य स्काउट्स के साथ विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर का संचालन राज्य संगठन आयुक्त पूरन सिंह शेखावत, सी ओ एल.आर.शर्मा व सहायक स्काउट प्रभारी योगेश कुमार के निर्देशन में हुआ। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोदार उ.मा. विद्यालय जयपुर के प्रधानाचार्य महेश वाधवानी ने इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की सफ्लता पर शुभकामना दी है।

मोदी को रास आया जालोर के बेटे का यह सुझाव

जालोर। जिले के एक फीजियोथैरेपिस्ट की ओर से दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए सुझाव को ना केवल सराहा गया है बल्कि सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इस प्रस्ताव पर चर्चा कर योजना को साकार रूप देने की तैयारी की जा रही है। जिले के मुड़तरासिली निवासी फीजियोथैरेपिस्ट डॉ. अभिषेक रावल की ओर से केंद्र सरकार को प्रत्येक जिला व तहसील मुख्यालय पर फीजियोथैरेपी सेंटर की शुरुआत करने का सुझाव दिया गया। जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए राजस्थान के मुख्य सचिव से चर्चा कर इसकी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पर लिए जाने वाले निर्णय के बारे में पीएम ऑफिस व डॉ. रावल को अवगत कराने को कहा है।

डॉ. रावल के इस सुझाव में बताया गया कि देश भर में जन्मजात विकृति वाले दिव्यांग सेरेब्रल पाल्सी बच्चे ब्रेन हेमरेज ट्रोमा व लकवा से पीड़ित दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से पेंशन तो दी जा रही है, लेकिन उनके उपचार के लिए आज तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। ऐसे मरीजों को भौतिक चिकित्सा फीजियोथैरेपी से उपचार कर फिर से नई जिंदगी दी जा सकती है। आज भी कई माता-पिता ऐसे दिव्यांग बच्चों को गोद में उठाकर घूमने पर विवश हैं या फिर ये बच्चे जमीन पर रेंगकर चलते हैं। अगर जिला और तहसील मुख्यालय पर फीजियोथैरेपी सेंटर शुरू किया जाता है

ऐसे दिव्यांगों की विकृति को हमेशा-हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है।

डॉ. रावल ने केंद्र सरकार को पहला पत्र 8 नवंबर 2015 को लिखा। जिसमें जिला व तहसील मुख्यालय पर फीजियोथैरेपी सेंटर खुलने से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। इस पत्र में बताया गया कि इस चिकित्सा से रोगी को ऑपरेशन तक की आवश्यकता नहीं पड़ती और वह कम ही समय में हमेशा के लिए स्वस्थ हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या दिव्यांग इस भौतिक चिकित्सा के लिए रोजाना लंबी दूरी तय नहीं कर सकता और इसके लिए उसके पास इतनी राशि भी नहीं होती। ऐसे में इन सेंटर के खुलने से रोगियों को आवागमन में सुविधा के साथ आर्थिक रूप से भी परेशान नहीं होना पड़ेगा।

डॉ. रावल जिला मुख्यालय पर संचालित जिला नि:शक्तजन पुनर्वास केंद्र व भीनमाल स्थित खुद के निजी अस्पताल में कई लकवा और हड्डी रोगियों का इलाज कर रहे हैं। इसके बाद हाल ही में जिला मुख्यालय पर उनकी ओर से फीजियोथैरेपी सेंटर शुरू किया है। जहां वास्तविक गरीब मरीजों का निशुल्क उपचार किया जा रहा है।

मैनें पीएम को हर जिला व तहसील मुख्यालय पर फीजियोथैरेपी सेंटर की शुरुआत का सुझाव लिखित में भेजा था। जिसके बाद गत 6 जुलाई को पीएम ऑफिस की ओर से हैल्थ सैक्रेटरी को इस बारे में निर्णय लेकर अवगत कराने को कहा है। अगर इस पर सकारात्मक निर्णय लिए जाते हैं तो इसकी शुरुआत राजस्थान से हो सकेगी। इससे दिव्यांगों को काफी फायदा मिलेगा।

-डॉ. अभिषेक रावल, फिजियोथेरेपिस्ट

कलेक्ट्री में खुला मार्गदर्शन केंद्र, दिव्यांगों को अब नही लगना होगा लाइन में

धमतरी। कलेक्टोरेट पहुंचने वाले दिव्यांगों के लिए आवक-जावक के पास दिव्यांगजन मार्गदर्शन केंद्र खोला गया है। कलेक्टर सीआर प्रसन्ना ने इसका शुभारंभ किया। जनदर्शन में भी दिव्यांगजनों को लाइन में लगकर अपनी पारी का इंजतार करना पड़ता था। पूर्व में यह वेटिंग रुम के रूप में उपयोग हो रहा था। शिकवा शिकायत लेकर कलेक्टोरेट में बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचते हैं। लेकिन इनके बैठने के लिए यहां कोई उचित स्थान नहीं था।

कलेक्टर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन मार्गदर्शन केंद्र खोला गया है। यहां विभाग द्वारा दो कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण कर रहे हैं। पहले दिन ही यहां 20 दिव्यांग पहुंचे। परसुली के लालचंद निषाद ने मोटराइज्ड ट्रायसिकल मांगा। रावां की लीलाबाई विधवा पेंशन की मांग लेकर पहुंची थी। एक निशक्त को ट्रायसिकल तथा एक को बैसाखी वितरण किया गया।

सुमेरपुर में 40 दिव्यांगों को वितरित की व्हील चेयर और ट्राई साइकिल

सुमेरपुर। ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में पंचायत समिति परिसर में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन ताल्लुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुमेरपुर अध्यक्ष मंजु चौहान की अध्यक्षता में हुआ।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण कुमार चौहान, एसडीएम महिपाल कुमार भारद्वाज, प्रधान राजेंद्रसिंह कोलीवाड़ा, पालिकाध्यक्ष जोराराम कुमावत, उपप्रधान करणसिंह नेतरा आदि उपस्थत थे। चौहान ने बताया कि न्याय पालिका जनता की समस्याओं का समाधान विभिन्न शिविर लगाकर कर रही है, जिसमें लोगों के दावों का आपस में समझाइश से निस्तारण, महिलाओं एवं पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से किया जाता है। उन्होंने आमजन को लोक अदालत की भावना तथा आपसी समझाइश से अपने वादों का निस्तारण करवाने के लिए प्रेरित किया।

ट्राई साइकिलों का किया वितरण

शिविर में 775 श्रमिक कार्ड वितरण, विधवा पेंशन के 40 पीपीओ, वृद्धावस्था पेंशन के 150 पीपीओ, विशेष योग्यजन पेंशन के 35 पीपीओ जारी तथा विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 40 व्हील चेयर एवं ट्राई साइकिलें दी गई।

तोषियास संस्था करेगी दिव्यांगों की मदद

पटना। जी-8 नंदन टॉवर स्थित तोषियास संस्था के कार्यालय में सभा का आयोजन किया गया। इसमें 28 जिलों के दिव्यांग ने भाग लिया। संस्था के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि जिन दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे पास, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड आदि नहीं बन पा रहा है उन सभी की मदद तोषियास संस्था करेगी। इन सभी प्रमाणपत्रों को संस्था द्वारा नि:शुल्क बनवाया जाएगा। इसके लिए 9122959613 पर संपर्क किया जा सकता है।

अब श्रवण बाधित दिव्यांग महिला आईटीआई में सीखेंगी ड्रेस मेकिंग

उज्जैन। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अब श्रवण बाधित दिव्यांगों को कौशल उन्नयन व रोजगार मूलक प्रशिक्षण के तहत ड्रेस मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला आईटीआई में श्रवण बाधित दिव्यांगों के लिए खासकर ड्रेस मेकिंग (एनसीवीटी) के तहत 21 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है। वेबसाइट पर आईटीआई काउंसिलिंग की समय-सारिणी और रिक्त सीटों की जानकारी सहित प्रवेश विवरणिका भी उपलब्ध है।

दिव्यांगों को नि:शुल्क सिलाई प्रशिक्षण व सिलाई मशीन

उदयपुर। नारायण सेवा संस्थान में नि:शक्त व निर्धनजन के लिए चलाए जा रहे व्यवसायोन्मुखी विभिन्न प्रशिक्षणों के अन्तर्गत द्विमासिक नि:शुल्क सिलाई प्रशिक्षण का समापन संस्थान संस्थापक कैलाश मानव के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। संस्थान निदेशक श्रीमती वंदना अग्रवाल ने सभी 19 प्रशिक्षणार्थियों को प्रारंभिक रोजगार के लिए सिलाई मशीनें व वस्त्र प्रदान किए। प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रशिक्षिका नसरीन बानू ने प्रस्तुत किया। संचालन पलक अग्रवाल ने किया।

डिवाइस से कंट्रोल होगा शुगर लेवल, पैंक्रियाज ट्रांसप्लान्ट की जरूरत नहीं

लंदन। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक अनोखी डिवाइस बनाई है। जिसका नाम आर्टिफिशियल पैंक्रियाज है। यह ऑटोमैटिक डिवाइस है। इसे पहनने से ब्लड में शुगर का लेवल अपने आप कंट्रोल में रहेगा। टाइप-2 स्टेज के डायबिटीज मरीजों को इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लगवाना पड़ेगा।

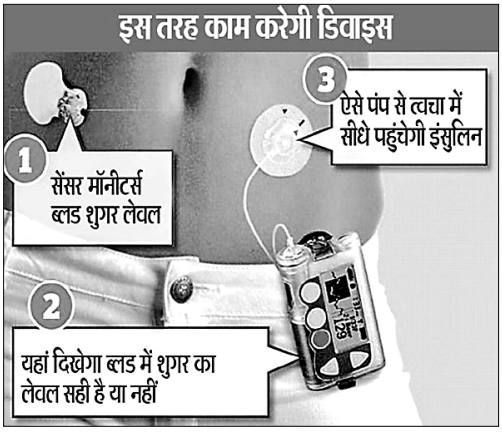

डिवाइस अगले साल तक बाजार में होगी। जानिए कैसे काम करती है ये डिवाइस-

दरअसल, डिवाइस को ऑन करते ही ये शरीर में ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना शुरू कर देती है। फिर जरूरत पड़ने पर रेग्युलर इंटरवल पर डायबिटीज मरीज की स्किन में इंसुलिन को पैचेज के जरिए भेजती रहती है। इसका साइज आईफोन जैसा है। इसे शरीर में कपड़ों के नीचे आसानी से पहना जा सकता है।

हालांकि, डिवाइस की कीमत अभी नहीं बताई गई है। भारत में करीब पांच करोड़ डायबिटीज मरीज हैं। इसके चलते ज्यादातर लोगों को समय-समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना होता है। वहीं ए टाइप-2 स्टेज के मरीजों को कई बार हर घंटे उंगलियों में इंजेक्शन के सहारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल का टेस्ट करना होता है।

ये है डिवाइस की खासियत

इस डिवाइस की एक और खासियत है कि यह न केवल मरीज के ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगी, बल्कि इससे उसका लेवल भी देखा जा सकता है। डिवाइस के टेस्ट के दौरान तीन महीने तक मरीजों को इसे पहनाने के बाद देखने को मिला कि उनके ग्लूकोज का लेवल 11 फीसदी तक बढ़ गया।

टीम में शामिल डॉ.होवोरका बताते हैं कि इस डिवाइस को बनाने का अधिकार हमने हासिल कर लिया है। इसे जल्द से जल्द बाजार में लाया जाएगा। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सके। टेस्ट में डिवाइस के इस्तेमाल से कई डायबिटीज मरीजों को पेंक्रियाज ट्रांसप्लान्ट तक नहीं करवाना पड़ा। जबकि डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी करवाने को बोल रखा था।

बदल देगी डायबिटीज मरीजों की जिंदगी

यूके की डायबिटीज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉ.एलिजाबेथ रोबर्टसन कहती हैं कि यह डिवाइस डायबिटीज मरीजों की जिंदगी को बदल देगी। खासकर उन मरीजों को काफी मदद मिलेगी, जो भाग-दौड़ के चलते ग्लूकोज व शुगर लेवल को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। खुश होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने हमें इतनी बेहतरीन डिवाइस दी है।

स्कूल के पाठ्यक्रम में विकलांगता पर अध्याय जल्द : जावड़ेकर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान उच्च अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया। चित्र में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर एक दिव्याग छात्र को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए। साथ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव डॉ. सुभाष चंद्र खुंटिया भी हैं।

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं के बीच अशक्तता के बारे में जागरुकता बढ़ाने और इस मुद्दे के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए जल्द ही स्कूली पाठ्यक्रमों में इस पर अध्याय शामिल किए जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दिव्यांगों के लिए वैश्विक पहुंच सुविधा के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए यहां आयोजित बाइकर्स की एक रैली में जावड़ेकर ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांगों की पहुंच लायक बनाया जाएगा।

इंडिया गेट से रवाना की गई इस रैली में शहर के अग्रणी बाइकर्स समूहों ने हिस्सा लिया। इस रैली का आयोजन दिव्यांग लोगों से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान के तहत किया गया।

मुख्यमंत्री का आधिकारिक मोबाइल एप लॉन्च

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने होटल मेरियट में अपना आधिकारिक मोबाइल एप लॉन्च किया। इस एप के माध्यम से प्रदेशवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की ताजा जानकारी मिल सकेगी। 'वसुन्धरा राजे' मोबाइल एप के माध्यम से आमजन मुख्यमंत्री के साथ सीधा संवाद भी कर सकेंगे और दस्तावेज या फोटो अपलोड कर सकेंगे। इस एप में इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी एवं शिकायत समाधान सिस्टम भी है। साथ ही, राज्य सरकार अन्य एप्स के लिंक एवं राजस्थान के विकास से जुड़े इंफोग्राफिक्स उपलब्ध हैं। इस एप के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में आर्थिक सहयोग किया जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री के भाषण, संदेश एवं साक्षात्कार भी उपलब्ध हैं।

अब घर बैठे भी ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकेंगे दिव्यांग

पटना। दिव्यांगों को आरक्षण टिकट कटाने में होने वाली परेशानी को देखते हुए रेलवे ने उनको नयी सुविधा प्रदान की है। इसके तहत रेलवे अपने स्तर पर दिव्यांगों का फोटो आई कार्ड बनायेगा, जिसकी मदद से वे घर बैठे भी ऑनलाइन आरक्षण टिकट बुक करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसकी कॉपी सभी जोनल कार्यालयों के मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को भी भेजी गयी है।

अस्पताल के प्रमाणपत्र पर बनेगा फोटो आइडी रेलवे द्वारा निर्गत किया जाने वाला फोटो आइडी राज्य या केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल, क्लीनिक व चिह्नित संस्थानों द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया जायेगा। इसके लिए संबंधित दिव्यांग को मंडल कार्यालय में सीनियर डीसीएम के पास आवेदन करना होगा। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक स्तर पर उनको फोटो आइडी कार्ड जारी कर दिया जायेगा।

दूसरे जोन का प्रमाण पत्र भी मान्य: अगर दिव्यांग यात्री का विकलांगता प्रमाण पत्र किसी दूसरे जोन का बना है और वह वर्तमान में किसी दूसरे जोनल रेलवे क्षेत्र का निवासी है तो वैसी परिस्थिति में आवेदक को वर्तमान जोन के संबंधित मंडल रेल कार्यालय में आवेदन करना होगा। उनके आवेदन को संबंधित जोनल कार्यालय वेरिफाइ कर वर्तमान जोन को रिपोर्ट करेगा। ऐसे केस में यह प्रक्रिया अधिकतम दो महीने में निश्चित रूप से पूरी कर लेनी होगी।

पांच साल के लिए वैध होगा फोटो आइडी: रेलवे का फोटो आइडी सामान्य परिस्थिति में पांच साल के लिए अथवा छूट प्रमाण पत्र की वैधता की अंतिम तिथि तक वैध होगा।

बहुत हो चुका,अब जाने भी दो ना ....

30 सर्जरी और रोज 12 घंटे वेंटिलेटर पर रहने के बाद लड़की ने मांगी इच्छामृत्यु

विस्कोसिन (अमेरिका)। यह 14 साल की जेरिका बोलेन है। जब आठ महीने की थी तभी से इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 2 नामक गंभीर बीमारी हो गई थी। तब से अब तक 30 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। रोजाना 12 घंटे वेंटिलेटर पर रहती है। लेकिन इसका दर्द कभी कम नहीं हुआ।

हाल ही में एक बड़ी सर्जरी हुई तो दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। अब तो डॉक्टरों ने भी हार मान ली। आखिरकार जेरिका ने कहा.. बहुत हुआ दोस्तो! अब मुझे जाने दो। इच्छामृत्यु का फैसला ले लिया। अगस्त में उन्हें मौत मिल जाएगी।

मां जेन बोलेन कहती हैं, इतना दर्द होने के बावजूद वो हमेशा खुश रहती है। वह इस दर्द के साथ बड़ी हुई। अब वह इतनी बड़ी है कि अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन इसके पहले उसने अपने दोस्तों के साथ डांस पार्टी की इच्छा जताई। परिवार ने ऐसा ही किया। इस डांस पार्टी में जेरिका क्वीन की तरह सजकर आई। उसने जमकर जश्न मनाया।

मैं दुनिया में सबसे स्ट्रांग हूं

मैंने बहुत आंसू बहा लिए। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं महसूस कर रही हूं कि अच्छी जगह जा रही हूं। इस बीमारी के लिए भगवान ने मुझे शायद इसलिए चुना क्योंकि मैं दुनिया की सबसे मजबूत लड़की हूं।